बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 24 ● अंकः 118 ● नई दिल्ली ● बुधवार 18 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

जे.सी. बोस विश्वविद्यालय में ट्रांसमीडिया स्टोरीटेलिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 18-19 फरवरी को

चंडीगढ़ । जे.सी.बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद में 18-19 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ट्रांसमीडिया स्टोरीटेलिंगः नैरेटिव्स, डिस्कोर्स एंड डिसेमिनेशन (टीएस-26) की तैयारियाँ इन दिनों अपने अंतिम चरण में हैं। साहित्य एवं भाषा विभाग की अध्यक्षा प्रो दिव्यज्योति सिंह ने बताया कि यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित विद्वान ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमों से सहभागिता करेंगे। उन्होंने बताया कि आज के वैश्विक और डिजिटल युग में कहानी कहने की प्रक्रिया पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर बहुस्तरीय और बहुआयामी स्वरूप ग्रहण कर चुकी है।

दिल्ली हादसा : ओवर-स्पीडिंग के 13 चालान, नाबालिग दौड़ा रहा था कार; मां के बाद साहिल के दोस्त ने खोला बड़ा राज

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली में एक भीषण सड़क दुर्घटना ने 23 वर्षीय साहिल धनेशा की जान ले ली। हादसा दिल्ली के द्वारका साउथ थाना इलाके में 3 फरवरी को हुआ। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में एक टैक्सी चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन को सुबह 11:57 बजे इस हादसे की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पहले साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी से जा टकराई। इस भयावह टक्कर में साहिल धनेशा ने दम तोड़ दिया, जबकि टैक्सी चालक को गंभीर चोटें आईं।

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि स्कॉर्पियो कार का चालक एक 17 वर्षीय नाबालिग था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि उसे बोर्ड परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। इस घटना ने नाबालिगों द्वारा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और यातायात नियमों की अनदेखी के गंभीर मुद्दे को उजागर किया है।

मां की व्यथा और न्याय की मांग

साहिल की मां, इन्ना माकन, इस हादसे से गहरे सदमे में हैं और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जिस स्कॉर्पियो ने उनके बेटे को कुचला, उस पर पहले से ही ओवर-स्पीडिंग के 13 चालान थे। इसके बावजूद, वाहन के मालिक (जो कि आरोपी चालक के पिता हैं) ने उसे नहीं रोका। इन्ना माकन ने बताया कि उनका बेटा 3 फरवरी को

ऑफिस जा रहा था, जब यह दुर्घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कॉर्पियो चालक बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था, और उसकी बहन साथ में बैठकर रील बना रही थी। गाड़ी उल्टी लेन में चलाई जा रही थी और बस के सामने स्टंट करने का प्रयास किया गया, जिससे यह भयानक हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक आपराधिक कृत्य है, जिसमें उनके बेटे की जान चली गई। इन्ना माकन ने सोशल मीडिया पर भी अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने अपने 22+ वर्षीय प्रतिभाशाली बेटे साहिल धनेशा को एक सिंगल मॉम के तौर पर 23 साल तक पाला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक कार चालक और उसकी बहन ने रील बनाने के चक्कर में उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक साहिल के दोस्त मानव सचदेवा ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना मेहनती इंसान कभी नहीं देखा। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई दूसरा दोस्त अपने परिवार और अपने लिए इतनी मेहनत करता होगा।

मुझे उसकी मां से इशारा मिला था। वे शायद उसे मैनचेस्टर या जर्मनी भेजना चाहते थे। उसने मुझसे इस बारे में पूछा। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा पूरा परिवार यहीं है और मेरा पूरा बिजनेस यहीं सेट अप है। दोस्त ने बताया कि हम अभी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमारी मांग यह है कि सबसे पहले, उसे कुछ समय जेल में रहना चाहिए और उसने जो किया उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि अगर दो लोगों ने दो जानें ले लीं तो उसके साथ क्या होता है। उसके पिता को याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने बेटे को बिना लाइसेंस वाली कार में भेजा था। वहीं, हादसे में घायल कैब ड्राइवर अजीत सिंह ने कहा कि मैं लाल बहादुर कॉलेज के पास इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से एक स्कॉर्पियो आई और मेरी कार को टक्कर मार दी और मेरी कार आगे जाकर बस से टकरा गई। कुछ बच्चों ने मुझे कार से बाहर निकाला और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद, उन्होंने टांके लगाए और करीब 4 बजे मुझे छुट्टी दे दी... मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला इंसान हूं। डॉक्टरों के मुताबिक, मैं अगले 5-6 महीने तक काम नहीं कर पाऊंगा। तब तक, परिवार और मेरा क्या होगा?।

दिल्ली के पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, एक की मौत और दूसरा गंभीर घायल

पश्चिमी दिल्ली। पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 24 वर्षीय विजय की मौत हो गई और एक अन्य युवक मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को वेस्ट दिल्ली के पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर दोपहिया से जुड़े एक रोड एक्सीडेंट में 24 साल के एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह 8.10 बजे मिली पीसीआर कॉल पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल खराब हालत में पड़ी मिली। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मौके पर दो घायल लोग मिले, जिन्हें आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने बताया कि घायलों में से एक, रोहिणी के सेक्टर 20 का रहने वाला विजय को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि जबकि मोनू को उसकी हालत गंभीर होने की वजह से तुरंत सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरी जांच कर रही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज देखना और चश्मदीदों के बयान इकट्ठा करना शामिल है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई और गाड़ी भी शामिल थी या नहीं।

डीयू में यूजीसी विवाद की बीच लिया गया बड़ा फैसला, जुलूस और प्रदर्शन पर 1 महीने तक लगी रोक

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक महीने के लिए पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन और किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार द्वारा विद्यार्थियों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ के लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 17 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और अगले एक महीने तक लागू रहेगा. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह कदम कैंपस में कानून-व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उठाया गया है. आदेश के तहत किसी भी प्रकार की सभा, रैली, विरोध प्रदर्शन या सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने सभी छात्रों और कर्मचारियों से नियमों का पालन करने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है. विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार ने आदेश में जारी किया है कि डीयू परिसर में बिना रोक-टोक के सार्वजनिक समारोहों, जुलूस या प्रदर्शन से ट्रैफिक में रुकावट, इंसानी जान को खतरा और जनशांति भंग हो सकती है. उन्होंने कहा कि पहले भी आयोजक अक्सर ऐसे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है. प्रॉक्टर ने अपने आदेश में यह भी बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सब-डिवीजन सिविल लाइंस ने भी 26 दिसंबर, 2025 को इस आशय में एक आदेश जारी किया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट भारत सरकार के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है. इसके अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी पब्लिक मीटिंग, रैली, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन अथवा किसी भी ऐसी गतिविधि पर रोक लगाई गई है जिससे कि आम लोगों की शांति या ट्रैफिक की सुगम आवाजाही पर असर पड़ सकता है यह आदेश 17 फरवरी 2026 से लागू है और एक महीने तक लागू रहेगा.

माहौल जहरीला हो रहा है - नेताओं के भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी नसीहत, कहा- देश में भाईचारा बढ़ाएं

नई दिल्ली ।

देश में नेताओं के भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए। कोर्ट ने शिक्षाविद् रूप रेखा वर्मा समेत 12 याचिकाकर्ताओं से राजनीतिक भाषणों पर दिशानिर्देश के लिए एक नई याचिका दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस

जयमाल्य बागची की बेंच ने मौजूदा जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में नेताओं और मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी। याचिककर्ताओं का कहना था कि कुछ नेताओं के भाषण भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। याचिककर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि देश में माहौल जहरीला होता जा रहा है। यह याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के कथित हेट स्पीच के संदर्भ में दायर की गई थी। सिब्बल ने दलील दी कि किसी एक नेता के खिलाफ राहत नहीं मांगी जा रही है, बल्कि भाषणों में जवाबदेही तय करने के लिए गाइडलाइन बनाने का अनुरोध किया गया है।

आप सोच को कैसे कंट्रोल करते हैं, हेट स्पीच से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की हेट स्पीच के खिलाफ कड़े दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने तीन मुख्यमंत्रियों के विवादास्पद बयानों का जिक्र करते हुए याचिका को पक्षपाती बताते हुए संशोधन की सलाह दी। इस याचिका में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लिया गया था। ये तीनों नेता भाजपा से जुड़े हैं याचिका को पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नागरिक समाज के प्रमुख सदस्यों के एक बड़े समूह ने दायर किया था। सरमा के हालिया मिया मुसलमानों वाले बयान, धामी द्वारा लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल और आदित्यनाथ की उर्दू समर्थकों पर दी गई टिप्पणियों को याचिका में प्रमुखता से उठाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, हमारा सुझाव है कि यह पिटीशन वापस ले ली जानी चाहिए और एक सिंपल पिटीशन फाइल की जानी चाहिए कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियां खुलेआम इसका उल्लंघन कर रही हैं।

पाकिस्तान की छटपटाहट

अगर कहा जाए कि मौजूदा अमरीका के पास 'ट्रम्प कार्ड' है जो कब चल दे, कोई नहीं जानता, तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का तल्खी भरा कहें या दर्द भरा बयान यही बताता है। गत दिवस वह नेशनल असेंबली में अमरीका की पाकिस्तान के प्रति भूमिका पर बोलते समय कुछ ऐसा बोल गए, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान को अपने सामरिक हितों के लिए हमेशा इस्तेमाल किया, उसके बाद टॉयलेट के पेपर जैसा छोड़ दिया। निश्चित रूप से इतना तो समझ आता है कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में बेचैनी जरूर दिख रही थी। अन्दरूनी तौर पर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ और परेशान होगा, यह लगता नहीं था। अमरीका ने इस्लाम को इस्लाम के खिलाफ खड़ा कर अपना मतलब साध लिया और स्वार्थी पाकिस्तान समझते हुए भी अनजान बना रहा। जब भारत से अमरीका की चंद दिनों पहले की नजदीकी समझ आई तो दर्द छलकने लगा। पाकिस्तान अच्छे से समझता था कि अफगानिस्तान की जमीन पर लड़े गए दो युद्ध न तो इस्लाम के हित में थे न ही मजहब से प्यार करने वालों के। हकीकत में ये दुनिया का दारोगा कहलाने वाले अमरीका के स्वार्थ से जुड़े थे, जो वास्तव में एक सुपरपावर की रणनीतिक जंग थी। निश्चित रूप से अब लगने लगा है कि पाकिस्तान-अमरीका के बीच मुनीर और शहबाज शरीफ के चापलूसी भरे रिश्ते पर भी अमरीकी राष्ट्रपति का ट्रम्प कार्ड चल गया है। खिसियाए पाकिस्तान और उसके रक्षा मंत्री के बयान के बाद, अब अंतर्राष्ट्रीय मायने चाहे जो निकाले जाएं लेकिन यह समझ आने लगा है कि पाकिस्तान की स्थिति 'उगलत लीलत पीर घनेरी' जैसी हो गई है, जाए तो जाए कहां? हालांकि ख्वाजा आसिफ अब मानते हैं कि पाकिस्तान ने सोवियत संघ के खिलाफ और 2001 के बाद अमरीका के नेतृत्व वाले युद्धों में भाग लिया था जो धार्मिक जेहाद कहते नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह राजनीतिक लाभ और दुनिया की बड़ी शक्तियों का समर्थन प्राप्त करने बाबत था। आर्थिक रूप से टूट चुके और एक तरह से आंतरिक युद्ध के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को पहले ही समझना था कि ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। बहरहाल मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ट्रम्प की चापलूसी कर-कर के बनाए गए संबंधों में न केवल कड़वाहट आ रही, बल्कि कीड़े भी पड़ रहे हैं। शायद पाकिस्तान यह भूल गया है कि अच्छा पड़ोसी उसका सही हितैषी होता है। लेकिन उसने तो शुरू से भारत को अपना दुश्मन मान रखा था, जिसके नतीजे अब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान खुद ही अपने बुने जाल में फंस कर कैसे फड़फड़ा रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसी से समझ आती है कि उसके मौजूदा हुक्मरान खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। अब आसिफ द्वारा की गई आलोचना उनकी छाती पीटने वाली मानसिक स्थिति जैसी है। वे इतने परेशान और व्यग्र हैं कि पूर्व सेना प्रमुखों जनरल जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ की खुलकर आलोचना करते हुए यह कहने से भी नहीं हिचकते कि दोनों ने अमरीका को अफगानिस्तान युद्ध के लिए अपना पोर्ट और एयरस्पेस देकर दोगलई की। दोनों ने इस लड़ाई की खातिर अपनी रीति-नीति भी बदल दी, जिसे आज पाकिस्तान भुगत रहा है। अब आसिफ को अफगानिस्तान की तबाही याद आने के साथ-साथ खुद की गलतियां भी नजर आने लगी हैं, जिसके चलते न केवल लाखों लोग प्रभावित हुए, तबाह हुए, बल्कि पीढ़ियां भी बर्बाद हुईं। वे इसे पाकिस्तान का 'यूज एंड थ्रो' बताते हुए यहां तक कहते हैं कि हकीकत में यह किराए का एक युद्ध था, जिसमें पाकिस्तान का अमरीका ने अपने सामरिक हितों के लिए खासा इस्तेमाल किया और मतलब निकलते ही छोड़ दिया। यकीनन टुकड़े फैंक कर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। क्या यह सब भारत के साथ हुई डील के बाद पाकिस्तान को समझ आया? पाकिस्तान जब झोली लेकर भीख मांगते हुए अमरीका के सामने खड़ा होता था, तब यह पुरानी बातें याद क्यों नहीं रहती थीं? जब तक उसकी झोली में अमरीकी डॉलर बतौर भीख आते रहे तो मुंह बंद रहता था। तब भी क्या पाकिस्तान इतना अनजान था? अमरीका की भारत के प्रति नरमी कहें या नए व्यावसायिक क्षेत्र में साथ आने का इशारा, उससे भी पाकिस्तान परेशान है। इधर अमरीका ने दक्षिण एशिया और पश्चिमी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, जो हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री और भू-राजनीतिक क्षेत्र है और अफ्रीका के पूर्वी तट से अमरीका के पश्चिमी तट तक फैला है, को लेकर जैसे ही भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया, पाकिस्तान को मानो सांप सूंघ गया। पाकिस्तान को डर क्यों लगा क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग और 65 प्रतिशत आबादी वाला क्षेत्र है, जो आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी एक-एक गलती याद आ रही है। उसके कई नेता इस बात पर छाती पीटते दिख रहे हैं कि अफगानिस्तान किन नीतियों से तबाह हुआ! अब वहां संसद में खुलेआम स्वीकारा जा रहा है कि दुनिया अनजान बनकर नहीं रह सकती। निश्चित रूप से पाकिस्तान-अमरीका संबंध एक खतरनाक मोड़ पर हैं। देर आयद दुरुस्त आयद का अलाप पाकिस्तान कब तक अलापेगा और इससे होगा क्या? दुनिया जानती है कि डोनॉल्ड ट्रम्प बतौर ट्रम्प कार्ड कब कौन सी चाल चल जाएं, कोई नहीं जानता!

सावरकर को 'भारत रत्न' देने की मांग को लेकर विवाद

हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे उनके विचारों, विश्वासों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर गहरे मतभेद सामने आए हैं। इस मुद्दे ने पहली बार 2019 में बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ा, जब भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश की, जबकि कांग्रेस ने इस पर तीखा हमला किया। यह मांग 2024 में भी फिर से उठी, जब शिवसेना (यू.बी.टी.) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। 1883 में नासिक के पास भगूर में दामोदर और राधाबाई सावरकर के घर जन्मे, उनकी शुरुआती जिंदगी उत्तरजीविता और व्यावहारिक चयनों से भरी थी, जैसे कि अंग्रेजों से बातचीत करना और दया याचिकाएं दायर करना, जिसने उनकी जटिल विरासत को आकार दिया। बहुत से लोग सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने अंडेमान की सेलुलर जेल से अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थीं। आलोचकों का मानना है कि ये याचिकाएं सालों की कुर्बानी से ज्यादा कमजोरी दिखाती हैं। टॉर्चर खत्म करके नॉर्मल जिंदगी में लौटना इंसान की एक स्वाभाविक इच्छा है। सावरकर ने शहीद बनने की बजाय जिंदा रहना चुना। उनका मानना था कि एक जिंदा क्रांतिकारी, भले ही उसे पाबंद किया गया हो, अंडेमान में मरे हुए हीरो से ज्यादा देश के लिए कर सकता है। सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से अपनी याचिकाओं में माफी नहीं मांगी। एक काबिल वकील होने के नाते, उन्होंने कैदियों की स्थिति पर सफाई मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस उलझनी जगह पर बिना यह जाने कि उन्हें आम कैदी माना जाता है या पॉलिटिकल कैदी, कैद कर दिया गया था। सावरकर को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो सकते और उन्हें रत्नागिरी जिले में ही रहना होगा। सावरकर ने खुद को एक समाज सुधारक के तौर पर पेश किया जो छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित थे, इस मुद्दे पर उन्होंने बहुत काम किया। हालांकि, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भूमिगत समर्थन भी बनाए रखा। उन्होंने रत्नागिरी में पतित पावन नाम का एक मंदिर बनवाया, जो सभी समुदायों और जातियों के लोगों के लिए खुला था। इस पहल से ऊंची जाति के हिंदू परेशान हो गए। हाल ही में नेहरू आर्काइव से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विनायक दामोदर सावरकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न न देने की सलाह दी थी। यह बात सावरकर की विरासत और इससे पैदा हुए राजनीतिक मतभेदों को लेकर चल रही बहस को और गहरा करती है। जून, 1963 में, नेहरू ने लिखा, "मैं आपका वह पत्र लौटा रहा हूं जिसमें श्री सावरकर को भारत रत्न देने का सुझाव दिया गया है। हालांकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था लेकिन बाद में वह विवादों में आ गए। मुझे नहीं लगता कि हमें यह सुझाव मानना चाहिए।" जबकि उस समय के कई सुधारकों ने हिंदू धर्म के ढांचे के अंदर 'अछूतों' को ऊपर उठाने की कोशिश की, सावरकर एक तर्कवादी थे, जो इस ढांचे को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने अपनी मान्यताओं के समर्थन के लिए कदम भी उठाए। उन्होंने पतित पावन मंदिर बनवाया, जो भारत के उन पहले मंदिरों में से एक था, जहां सभी जातियों के लोगों का स्वागत किया जाता था, जिनमें उस समय अछूत माने जाने वाले लोग भी शामिल थे। एक दलित पुजारी को नियुक्त करके और अंतरजातीय खाने और शादी को बढ़ावा देकर, उन्होंने सामाजिक नियमों को चुनौती देने की कोशिश की। उनकी कोशिशों का मकसद अलग-अलग समुदायों के बीच सम्मान जगाना, बराबरी को बढ़ावा देना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि सावरकर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर साजिश का आरोप लगाया गया था। फिर भी, 10 फरवरी, 1949 को, जज आत्मा चरण की अध्यक्षता वाली लाल किले की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सभी सबूतों की समीक्षा, जिसमें अप्रूवर दिगंबर बड़गे की गवाही भी शामिल है, इसमें शामिल कानूनी प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, किसी साथी के सबूत को भरोसेमंद होने के लिए स्वतंत्र सबूतों से पुष्टि की जानी चाहिए। प्रॉसिक्यूशन यह देने में नाकाम रहा।

सावरकर के पोते, रंजीत सावरकर ने केंद्र सरकार से अपने दादा के 'स्वातंत्र्यवीर' टाइटल की मान्यता देने की मांग की है, यह कहते हुए कि यह मोहनदास करमचंद गांधी को दिए गए 'महात्मा' टाइटल जैसा होगा। कई लोग सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करते हैं। इनमें कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां और कुछ लिबरल ग्रुप शामिल हैं। शिवसेना लंबे समय से इस सम्मान के लिए जोर दे रही है, और भाजपा भी इसका समर्थन करती है। वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए, उन्होंने सावरकर को यह सम्मान देने पर विचार किया लेकिन इसके खिलाफ फैसला किया।

सम्पादकीय...

'पिंक' और 'ब्लू' के बीच फंसी स्त्रियां

आम तौर पर यदि गर्भ में बच्ची हो, तो उसे बातचीत में पिंक-पिंक पुकारा जाता है। अपने देश में तो जन्म पूर्व बच्चे का लिंग जानना कानूनी अपराध है लेकिन पश्चिम में यह आम बात है। हां, वे भारतीय माता-पिता को इसे बताने से परहेज करते हैं। इसका कारण भारतीयों की विश्वभर में फैली यह बदनामी भी है कि वे यह पता चलते ही कि गर्भ में लड़की है, उससे निजात पाने की कोशिश करते हैं। यह भी ताज्जुब होता है कि स्त्रियों को पिंक पुकारा जाए। पिंक माने गुलाबी का मतलब खुशियां और कोमलता होता है लेकिन स्त्रियों की जिंदगी की मुश्किलों को देखते हुए उन्हें इस उपाधि से विभूषित करना जैसे उनकी चुनौतियों को किसी रैपर के नीचे दबाना मालूम पड़ता है। लेकिन शायद आप जानते ही होंगे कि कम्पनियां महिलाओं के लिए जो उत्पाद बनाती हैं, उनमें से अधिकांश पिंक रैपर में होते हैं। इन्हें तरह-तरह की खुशबुओं से भरा जाता है। इन्हें आकर्षक ढंग से पैक किया जाता है। यह भी बताया जाता है कि इस तरह के उत्पादों को लांच करके महिलाओं को स्पेशल फील कराया जाता है। इन उत्पादों को महिलाओं के लिए जरूरी कह कर भी बेचा जाता है। इसे उनकी जीवन शैली और बहुत बार अच्छे स्वास्थ्य से जोड़कर भी पेश किया जाता है। जबकि वास्तविक रूप में इनका स्वास्थ्य से कोई लेना-देना नहीं होता। कई ऐसे सर्वे करके यह निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि महिलाओं को यदि कोई ब्रांड या उत्पाद आकर्षित करता है, तो वे ज्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होती हैं। यह भी कहा जाता है कि उनके लिए जो चीजें बनाई जा रही हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है। उनमें बेहतरीन सामान का इस्तेमाल किया गया है। इन उत्पादों की कीमत भी अधिक होती है। इसे पिंक टैक्स कहा जाता है। यानी पुरुषों के मुकाबले महिला उत्पादों की कीमत कम्पनियां ज्यादा रखती हैं। कमाल है न कि सिर्फ महिला होने के नाते अधिक कीमत देनी पड़े। आखिर कौन सी अर्थ प्रणाली ऐसा कहती है। इसे लैंगिक समानता से भी जोड़ा जाता है, जबकि है यह असमानता। दरअसल यह कम्पनियों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिससे कि वे लैंगिक समानता की बातें करके महिलाओं की जेब से अधिक से अधिक पैसे निकाल सकें। महिलाओं के लिए तमाम तरह के उत्पाद बनाने वालों की सोच यह भी है कि वे अपने लिए बनाए गए सामान पर अधिक कीमत देने के लिए तैयार होती हैं। कई बार तो लगता है कि महिलाओं को शायद इस बात का पता ही नहीं है। और यह भी कि कीमतों की यह बढ़ोतरी या टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाता। इसे कम्पनियां ही तय करती हैं कि महिलाओं के उत्पाद पुरुषों के लिए काम आने वाले उत्पादों से महंगे बेचने हैं। ध्यान दें तो कम्पनियों की यह रणनीति उन महिलाओं के लिए है, जो शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं। जिनकी जेब में पैसा है, जो खरीदने का निर्णय स्वयं ले सकती हैं। ये स्त्रियां ही इन कम्पनियों की टारगेट हैं। लेकिन वे महिलाएं भी तो हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं हैं या इतने पैसे नहीं कमातीं कि एक से एक महंगे उत्पाद खरीद सकें।

सीधे भारत मंडपम से... क्या एआई के क्षेत्र में दुनिया को पछाड़ पाएगा भारत?

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे वैश्विक एआई सम्मेलन में दो दिन से चल रहे विचार मंथन से एक बात उभर कर आई है कि एआई के समक्ष खड़ी चुनौतियों के हल के लिए दुनिया भारत की ओर निहार रही है। देखना होगा कि सम्मेलन के अंत में दिल्ली डिक्लेरेशन से क्या निकल कर आता है। लेकिन यहां एक और बात की आवश्यकता महसूस हुई कि भारत को यदि इस क्षेत्र में नेतृत्व हासिल करना है तो बड़े निवेश और सरल तथा प्रभावी नीतियों की भी जरूरत है। देखा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अब केवल नई तकनीक का आकर्षण नहीं रही, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुकी है। दुनिया के बड़े देश इसे रणनीतिक साधन की तरह देख रहे हैं। डाटा, कंप्यूटिंग शक्ति और उन्नत चिप आज के दौर का नया तेल बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत के सामने मूल प्रश्न यह है कि वह एआई की दौड़ में केवल उपभोक्ता बन कर रहेगा या निर्माता और नेता की भूमिका निभाएगा। भारत ने पहले भी तकनीकी मोड़ पर सही फैसले लेकर इतिहास बदला है। नब्बे के दशक में सूचना तकनीक और सॉफ्टवेयर सेवाओं पर जोर देने से लाखों रोजगार बने, भारतीय कंपनियां दुनिया भर में छा गईं और देश को नई पहचान मिली। आज एक वैसा ही मोड़ फिर सामने है, लेकिन इस बार दांव कहीं बड़ा है। एआई न केवल सेवाओं को, बल्कि कारखानों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, दवा उद्योग, परिवहन और ऊर्जा व्यवस्था तक को बदल सकती है। यह समझना जरूरी है कि एआई एक ही तरह की चीज नहीं है। उपभोक्ता एआई, जैसे चैट टूल या मनोरंजन आधारित अनुप्रयोग, तेजी से लोकप्रिय होते हैं, पर इन पर अक्सर कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा हो जाता है। इसके विपरीत औद्योगिक एआई हर क्षेत्र के लिए अलग समाधान मांगती है। हर उद्योग का अपना डाटा, अपनी समस्या और अपना कामकाज होता है। इसलिए क्षेत्र विशेष मॉडल बनते हैं। यही भारत की ताकत बन सकती है, क्योंकि यहां उद्योगों की विविधता और पैमाना दोनों मौजूद हैं। उदाहरण के लिए दो पहिया वाहन उद्योग को लें। भारत दुनिया के सबसे बड़े दो पहिया बाजारों में है। यह क्षेत्र रोजगार, शहरीकरण और आय वृद्धि से जुड़ा है। अब इलेक्ट्रिक दो पहिया का चलन भी बढ़ रहा है। ऐसे में एआई आधारित मांग अनुमान, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता जांच और आपूर्ति प्रबंधन से भारी लाभ हो सकता है। मशीन लर्निंग सिस्टम खराबी का पहले ही संकेत दे सकते हैं। इससे ठहराव घटता है, लागत कम होती है और उत्पादन तेज होता है। दवा उद्योग में भी अवसर विशाल है। भारत जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है, पर गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती रहता है। एआई आधारित विजन सिस्टम उत्पादन के दौरान सूक्ष्म दोष पकड़ सकते हैं। डाटा विश्लेषण से प्रक्रिया स्थिर रखी जा सकती है। रोबोटिक ऑटोमेशन दोहराव वाले काम सुरक्षित और सटीक तरीके से कर सकता है। इससे भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी और ऊंचे मूल्य वाले बाजार खुलेंगे। लेकिन एआई की ताकत केवल सॉफ्टवेयर से नहीं आती, इसके लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति चाहिए, जो उन्नत चिप यानी जीपीयू से मिलती है। ये चिप बहुत महंगी होती हैं। एक उन्नत जीपीयू की कीमत लाखों रुपये तक जा सकती है। भारत ने हजारों जीपीयू लगाए हैं और डाटा केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष डाटा केंद्रों ने बिजली ग्रिड से भारी मात्रा में बिजली ली, जो किसी बड़े शहर की मांग के बराबर बैठती है। आने वाले वर्षों में यह मांग कई गुना बढ़ सकती है। यह भारत की बढ़ती डिजिटल क्षमता का संकेत है, पर साथ ही ऊर्जा चुनौती का भी। अगर भारत को एआई में अग्रणी बनना है तो केवल कुछ हजार जीपीयू काफी नहीं होंगे। अमेरिका आज भी इस क्षेत्र में आगे है। उसके पास विशाल डाटा केंद्र क्षमता है और वह उन्नत जीपीयू की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण वह तकनीकी बढ़त बनाए हुए है। चीन को रोकने की रणनीति में भी चिप आपूर्ति अहम रही है। चीन ने भी इस दौड़ को बहुत पहले समझ लिया था। उसने चिप निर्माण में भारी निवेश किया। उसकी बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने एआई चिप बना रही हैं। भले वे अभी सबसे उन्नत स्तर पर न हों, पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी बड़ी तकनीकी कंपनियां खुद चिप डिजाइन में उतर चुकी हैं। ऐसे माहौल में यदि भारत केवल पुराने स्तर की चिप बनाता रह गया तो वह पीछे छूट सकता है। तो क्या समाधान है? क्या हमें अपनी आकांक्षा घटा लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत अभी विकसित देशों से कम है।

जैसे जैसे लोग समृद्ध होंगे, उन्हें घरों में अधिक बिजली चाहिए होगी। अगर एआई के कारण बिजली महंगी हुई तो जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। यह चिंता सही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पीछे हट जाएं। दरअसल जरूरत बड़े सोच की है। भारत को एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, घरेलू चिप निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देना। इसके लिए नीति समर्थन, निवेश और कौशल विकास जरूरी है। दूसरा, ऊर्जा ढांचा मजबूत करना। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बेहतर ग्रिड और भंडारण तकनीक पर जोर देना होगा ताकि डाटा केंद्रों की मांग पूरी हो सके। इसके साथ ही एआई का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। मध्यम और छोटे उद्योगों तक भी पहुंचे। इसके लिए साझा प्लेटफॉर्म, क्लाउड ढांचा और क्षेत्र विशेष समाधान जरूरी हैं। सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों को मिल कर काम करना होगा। शोध संस्थान मॉडल विकसित करें, उद्योग वास्तविक समस्याएं और डाटा दें, और सरकार नियम, प्रोत्साहन तथा अवसंरचना दे। भारत को ऐसे नेतृत्व की भी जरूरत है जो अलग अलग पक्षों को जोड़ सके और भरोसा बना सके। एआई को नौकरी छीनने वाली नहीं, बल्कि नई क्षमता देने वाली तकनीक के रूप में समझाना होगा। कौशल प्रशिक्षण, पुन-प्रशिक्षण और शिक्षा सुधार पर जोर देना होगा। बहरहाल, अब सवाल यह है कि एआई की दिशा कौन तय करेगा? अगर भारत ने समय रहते साहसिक फैसले लिए, चिप निर्माण, ऊर्जा ढांचा और औद्योगिक एआई पर जोर दिया, तो वह केवल तकनीक का बाजार नहीं रहेगा, बल्कि दिशा देने वाला देश बन सकता है। आईटी क्रांति ने भारत को विश्व मंच पर जगह दी थी। एआई और उन्नत कंप्यूटिंग भारत को आर्थिक शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता के नए दौर में पहुंचा सकती है। अवसर हमारे सामने है। अब निर्णय और क्रियान्वयन हमारी जिम्मेदारी है।

भारत को एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, घरेलू चिप निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देना। इसके लिए नीति समर्थन, निवेश और कौशल विकास जरूरी है। दूसरा, ऊर्जा ढांचा मजबूत करना। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बेहतर ग्रिड और भंडारण तकनीक पर जोर देना होगा ताकि डाटा केंद्रों की मांग पूरी हो सके। इसके साथ ही एआई का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। मध्यम और छोटे उद्योगों तक भी पहुंचे। इसके लिए साझा प्लेटफॉर्म, क्लाउड ढांचा और क्षेत्र विशेष समाधान जरूरी हैं। सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों को मिल कर काम करना होगा। शोध संस्थान मॉडल विकसित करें, उद्योग वास्तविक समस्याएं और डाटा दें, और सरकार नियम, प्रोत्साहन तथा अवसंरचना दे। भारत को ऐसे नेतृत्व की भी जरूरत है जो अलग अलग पक्षों को जोड़ सके और भरोसा बना सके। एआई को नौकरी छीनने वाली नहीं, बल्कि नई क्षमता देने वाली तकनीक के रूप में समझाना होगा। कौशल प्रशिक्षण, पुन प्रशिक्षण और शिक्षा सुधार पर जोर देना होगा। बहरहाल, अब सवाल यह है कि एआई की दिशा कौन तय करेगा?

अपनी सफलता का ब्लू प्रिंट तैयार करें

प्रश्न ----आपका सौन्दर्य और आयुर्वेद की तरफ झुकाव कैसे हुआ और दिल्ली में आपके प्रारम्भिक जीवन में शहनाज़ आयुर्वेद की नींव रखने में आपका विज़न क्या रहा /

शहनाज़ हुसैन -----जब एक युवा मॉडल की केमिकल आई लाइनर की वजह से आँखों की रौशनी चली गई तो मेरा दिल पसीज गया /

इस घटना से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया जब मेने केमिकल युक्त सौन्दर्य प्रसाधनों की बजाय सुरक्षित हर्बल आयुर्वेदिक सौन्दर्य प्रसाधनों की तलाश शुरू की जोकि शरीर और स्वास्थ्य के लिए बेहतर हों / मुझे लगा की प्राचीन आयुर्वेदिक में विद्यमान बेशकीमती हर्बल जड़ी बूटियों के गुणों में सभी सौन्दर्य समस्याओं का सकारात्मक समाधान विद्यमान है /

और इसी से प्रेरणा पाकर मेने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को खोजना शुरू कर दिया और इनका सौन्दर्य प्रसाधनों में उपयोग शुरू कर दिया / मैंने 5000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता के गुणों को एक जार में भर कर बेचना शुरू कर दिया जिससे लोगों को जड़ी बूटियों के चमत्कारी स्वास्थ्यप्रद गुणों का अहसास हुआ

. प्रश्न ----पुरुष प्रदान उद्योग जगत में एक महिला उद्यमी के रूप में आपने किस तरह चुनौतियों का सामना किया ?

शहनाज़ हुसैन ----जब मैंने उद्योग जगत में एक उद्यमी के तौर पर कदम रखा तो तब महिलाओं की परिवार में भूमिका मात्र चूल्हा चौका संभालने तक ही थी / उस समय महिलाएं पति और परिवार में एक धुरी की तरह काम करती थी और उनका संसार परिवार तक ही सीमित था / लेकिन मैंने महिला की ऐसी परिभाषा गढ़नी शुरू कर दी जो ऊँचे ख्वाब देखती हो और जिंदगी में कुछ कर पाने की तमन्ना रखती हो / इस तरह से मैंने रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ कर एक नए संसार में प्रवेश किया जहां महिलाएं आजादी और इज्जत से रह सकती हैं और खुले में साँस ले सकें / इस तरह मेरी दुनिया को आयुर्वेदिक आधारित सुरक्षित हर्बल सौन्दर्य उत्पादों को प्रदान करने की जीवन यात्रा शुरू हुई / उस समय मार्किट में केमिकल आधारित उत्पादों की बाढ़ से थी जिनका बाजार पर जबरदस्त अधिपत्य था / इस तरह सुरक्षित सौन्दर्य उत्पादों की तलाश में अनेक महिलाओं के लिए मैं पथ प्रदर्शक बनी और स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों की खोज करने वाली महिलाओं में एक आशा की किरण जगी जिससे लोगों में सौन्दर्य के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा /

प्रश्न ---आप प्राचीन आयुर्वेद को सौन्दर्य की आधुनिक जरूरतों से कैसे जोड़ती हैं

शहनाज़ हुसैन -----आयुर्वेद में त्वचा और बालों से जुड़ी सभी सौन्दर्य समस्यायों का प्रकृतिक समाधान मौजूद है / आयुर्वेद के सिद्धान्त के अनुसार स्वास्थ्य शरीर में दोष(त्रिदोष) सन्तुलित होते हैं जिससे त्वचा और बाल सुन्दर दिखते हैं / इसलिए सही मायनों में सुन्दरता का मतलब संतुलित (त्रिदोष) के माध्यम से सुन्दर त्वचा ग्रहण करना है न की सौन्दर्य उत्पादों की मोटी परत लेपने से /मैंने हर्बल उत्पादों की लम्बी श्रृंखला तैयार की है जिसमें केमिकल कतई नहीं है जिन्हे बनस्पति / बगीचों के घटकों , प्रकृतिक जड़ी बूटियों , पौधों के अर्क , सुगन्धित तेलों से बनाया गया है जो पूरी तरह स्वास्थ्य बर्धक हैं और उनके उपयोग से प्रकृतिक तौर पर निखार उभर कर सामने आता है / आधुनिक सौन्दर्य जरूरतों जैसी कोई डिमांड नहीं है बल्कि अब लोगों का समग्र (होलिस्टिक) जीवन शैली और वैलनेस आधारित सौन्दर्य उत्पादों के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है / अब महिलाएं उनकी त्वचा के माध्यम से उनके रक्त में जा रहे सौन्दर्य उत्पादों के संघटकों के प्रति संजीदा हो रही हैं / अब ग्राहक प्रकृतिक संघटकों पर आधारित सौन्दर्य उत्पादों के प्रति संजीदा हो रहे हैं और आयुर्वेद आधारित उत्पादों को ही बरीयता प्रदान कर रहे हैं और यहीं मेरी ताकत है क्योंकि मैं इसी लाइन में पिछले 50 सालों से हूँ और मेरी यह यात्रा निरन्तर आगे बढ़ती जा रही है /

प्रश्न --आपने सिग्नेचर ट्रीटमेंट / उत्पाद बाजार में उतारे हैं / इनके पीछे का आयुर्वेदिक विज्ञान क्या है ?

शहनाज़ हुसैन -----यह कीमती जड़ी बूटियों से एकत्रित प्लांट स्टेम सेल हैं जिन्हें वैज्ञानिक विधियों से उत्पादों का स्वरूप दिया गया है और यह चेहरे की झुर्रियों को रोकने और जवां दिखने में सहायक होते हैं / जड़ी बूटियों के गुणों से यह स्किन सेल को पुनर्जीवित करके नई शक्ति प्रदान करते हैं , त्वचा की इलास्टिसिटी को मूल रूप में बहाल करते हैं , चेहरे की छाइयों और झुर्रियों को कम करते हैं जिससे आप जवां और ऊर्जावान दिखते हैं / मैंने कैंसर रोगियों के लिए केमोलिने उत्पाद लांच किया है जोकि हेयर आयल और त्वचा की क्रीम है / यह उत्पाद मैंने सामाजिक दायित्व के तौर पर उतारा है /यह विशेषकर महिलाओं के लिए उतारा है जोकि कीमो की बजह से बालों के खो जाने से भावुक तौर पर परेशान हो जाती हैं तथा मानसिक शारीरिक तौर पर परेशान हो जाती हैं / एक महिला ने मुझे इंग्लैंड से पत्र लिख कर बताया की कैसे केमोलिन क्रीम की मदद से उसकी त्वचा में सुधार आया और उसके परिवार जन और दोस्त उसको सराह रहे हैं / इससे उसका आत्म विश्वास और आत्म सम्मान बढ़ा / यह उत्पाद समस्या की जड़ पर काम करते हैं और प्रकृतिक होने की बजह से एडाप्टोजेन हैं जोकि शरीर को शारीरिक ,मानसिक और पर्यावरणीय तनाव से निपटने में मदद करते हैं / इससे शरीर को पूरी तरह उपचार मिलता है और समस्या का जड़ से निदान भी हो जाता है /

प्रश्न ----महज एक ब्यूटी सैलून से शुरुआत करके आज विश्व भर में आपके 3000 से ज्यादा सैलून हैं / विश्व पटल पर आपकी सफलता का राज क्या है ?

शहनाज़ हुसैन --------------- प्रकृतिक आयुर्वेदिक उत्पाद और उत्पादन में केवल शुद्ध हर्बल घटकों का प्रयोग मेरे ब्रांड की सबसे बड़ी शक्ति है / मेरा मानना है की हर्बल उपचार के माध्यम से ही सौन्दर्य समस्यायों की जड़ से इलाज किया जा सकता है और अब ज्यादातर लोग भी इसी विचार से सहमत हो रहे हैं जिसकी बजह से लोग हमारे उत्पादों को पसन्द कर रहे हैं और यही मेरी ताकत है / आज कल के उपभोक्ता स्वास्थ्य बर्धक उत्पादों को तरजीह दे रहे हैं / मैं सेहत और सौन्दर्य की कुंजी प्रदान करती हूँ /

प्रश्न ----आप आज की महिलाओं को क्या सलाह देंगी जोकि अपना उद्यम स्थापित करना चाहती हैं

शहनाज़ हुसैन -------अगर आप सफल उद्यमी बनना चाहती हैं तो सबसे पहले अपनी प्रतिभा में निखार लाएं और अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों और परेशानियों को जरूर ध्यान में रखें यह ज्यादा महत्वपूर्ण है की आप अपना रास्ता चुनें और पथ प्रदर्शक बनें न की भीड़ का हिस्सा बनें / अगला कदम अपनी सफलता का ब्लू प्रिंट तैयार करें और अपनी मंजिल पाने के लिए अपना रास्ता तय करें / बेजोड़ बनें और किसी की कॉपी न करें / मजबूत रहिये और आगे बढ़ने की सुदृढ़ इच्छा शक्ती रखिये / जहाँ जरूरत हो वहां सीखने से परहेज मत करिये ।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582083548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

एआई के शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे टीएमयू के 109 छात्र

मुरादाबाद।

भारत मंडपम में आयोजित पांच दिनी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के छात्रों का बड़ा दल मंगलवार की सुबह दो बसों से दिल्ली कूच कर गया है। इस डेलीगेशन का नेतृत्व डीन एकेडमिक्स प्रो. मंजुला जैन कर रही हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में 92 स्टुडेंट्स,17 प्री -इन्क्यूबीटी आदि शामिल हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवम् सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 20 देशों के राष्ट्रध्यक्ष, प्रधानमंत्री के संग- संग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दिग्गज सीईओ की गरिमामायी उपस्थिति रहेगी। समिट में माइक्रोसॉफ्ट से बिल गेट्स, रिलायंस समूह से मुकेश अंबानी, सुंदर पिचई के अलावा टाटा समूह, इन्फोसिस, बायोकॉन, एंथ्रोपिक, एनवीडिया, एक्सेंचर, गूगल समेत दुनिया के 100 दिग्गज आकर्षण के केंद्र होंगे। टीएमयू के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को महाकुंभ की संज्ञा देते हुए कहते हैं, इस समिट की मेजबानी पर हमें नाज़ है। उन्होंने उम्मीद जताई, एआई सम्मेलन का रोडमैप दुनिया के लिए

मील का पत्थर साबित होगा। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में 20 सत्र और सेमिनार्स होंगे,जिनमें एक सत्र में टीएमयू की डीन प्रो. मंजुला जैन भी अपना नज़रिया रखेंगी। भारत के शैक्षणिक परिदृश्य में एआई नवाचार के लोकतंत्रीकरण पर केंद्रित टीएमयू की एक समाधान-उन्मुख पैनल चर्चा सुषमा स्वराज भवन में शाम साढ़े पांच बजे से होगी। इस सत्र का संचालन टीएमयू की डीन एकेडमिक्स एवं तीर्थंकर महावीर इनोवेशन फाउंडेशन- टीएमआईएफ की निदेशक प्रो. मंजुला जैन करेंगी,जबकि इस सत्र में प्रमुख नवाचार एवम् उद्योग विशेषज्ञों में एफआईटीटी -आईआईटी, दिल्ली के एमडी डॉ. निखिल अग्रवाल, इजराइल की माया शरमन, जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डॉ. कविता सिंह और इकोसिस्टम एवं इनोवेशन स्ट्रेटेजी लीडर उत्कर्ष मिश्रा की सहभागिता रहेगी। विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा करेंगे कि शैक्षणिक संस्थानों के छात्र अपने विचारों और शोध को एआई आधारित समाधानों में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। समिट में यूनिवर्सिटी के तीन स्टार्ट्स अप के प्रेजेंटेशन की भी तैयारी है। टीएमयू के इस डेलीगेशन में बतौर समन्वयक तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी टीएमआईएफ के इन्क्यूबेशन मैनेजर प्रशांत सिंह, टीएमयू आईआईसी कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार वर्मा, सीसीएसआईटी से डॉ. प्रियांक सिंघल, सीओई से फैकल्टी निकिता जैन आदि भी शामिल हैं।

आयुष चिकित्सकों ने उठाईं समस्याएं

क्लीनिकों की लाइसेंस दरे तय किये जाने को लेकर महापौर एवं नगर निगम के अफसरों से की भेंट

मुरादाबाद। आयुष डॉक्टर्स के संगठन नीमा मुरादाबाद के एक प्रतिनिधिमंडल ने महापौर कार्यालय पर एक संबंधित अधिकारियो से भेंट की। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा बनाई गई वाणिज्यिक नियंत्रण उपविधि 2024 में जो शुल्क निर्धारण किया गया है उसमें प्राइवेट क्लिनिक के लिए 3000 रू. वर्ष की दरे तय की गई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पदाधिकारियों ने कहा कि आयुष चिकित्स्कों के क्लिनिक और एलोपैथिक चिकित्सक के क्लिनिक को एक ही श्रेणी में रखना न्यायसंगत नहीं होगा क्यूंकि आयुष चिकित्सक के क्लिनिक पर बेहद कम खर्च में उपचार की सुविधा दी जाती है तथा परामर्श शुल्क भी मरीज से नहीं लिया जाता है। फलस्वरूप आयुष डॉक्टर के क्लिनिक का वित्तीय लाभ अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठान की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। इसी आधार पर मांग की गई है कि आयुष चिकित्सकों कर क्लिनिक को लाइसेंस शुल्क से मुक्त रखने की व्यवस्था करें। इस पर मेयर विनोद अग्रवाल ने शुल्क पर विचार करने व आयुष चिकित्स्कों की समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दियाप्रतिनिधि मंडल में चेयरमैन डॉक्टर वीके रस्तोगी सीनियर फिजिशियन डॉक्टर कमल कुमार नीमा अध्यक्ष डा. शहाबुद्दीन, नीमा महासचिव डा. नाज़िम खान, कोषाध्यक्ष डा. आरिफ़ रहमान, डॉ प्रदीप सक्सेना डॉक्टर ए के शर्मा, डॉक्टर शोएब खान डा. रिज़वान, डा. शहहेदीन, डा.शुएब खान, डा. आज़म, डा. सलमान, डा. इंतेज़ार, डा आरिफ़ अज़ीम आदि उपस्थित रहे।

'व्यस्त जिंदगी में न छूटे सेहत'

दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के विशेषज्ञों ने दी निवारक जांच की सलाह

मुरादाबाद।

दिल्ली से मुरादाबाद पहुंचे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने व्यस्त जिंदगी में सेहत पर ध्यान नहीं छूटने की सलाह दी। उन्होंने स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए किडनी, दिल और लिवर रोगों पर चेतावनी देते हुए समय रहते जांच कराने के लिए कहा। मुरादाबाद के लोगों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और बीमारियों की समय रहते पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल (रजि.) के सहयोग से स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस पहल के तहत अपोलो के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने जीवनशैली से जुड़ी बढ़ती बीमारियों पर विस्तार से चर्चा की और समय-समय पर जांच व चिकित्सकीय परामर्श लेने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कार्यक्रम में स्थानीय व्यापारिक समुदाय, पेशेवरों और नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी की। इन विशेषज्ञ

डॉक्टरों ने नेफ्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. प्रो. संजीव जसूजा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी व हेपेटोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश बत्रा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. राजीव राजपूत और गाइनकोलॉजी ऑन्कोलॉजी विभाग से वरिष्ठ सलाहकार डॉ. पाखी अग्रवाल शामिल रहीं। चर्चा के दौरान डॉ. संजीव जसूजा ने मधुमेह और उ ंच रक्तचाप से जुड़ी बढ़ती किडनी बीमारियों पर चिंता जताई। वहीं, डॉ. योगेश बत्रा ने फैटी लिवर सहित पाचन तंत्र और लिवर रोगों के बढ़ते मामलों पर प्रकाश डाला। इस बीच एक सवाल पर जवाब देते हुए डॉ. राजीव राजपूत ने हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए नियमित कार्डियक स्क्रीनिंग की अहमियत के बारे में बताया। साथ ही डॉ. पाखी अग्रवाल ने महिलाओं में स्त्रीरोग संबंधी कैंसर की समय पर जांच और जागरूकता को बेहद महत्वपूर्ण बताया। नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के प्रबंध निदेशक शिवकुमार पट्टाभिरमन ने कहा, हम मानते हैं कि स्वास्थ्य जागरूकता महानगरों से बाहर भी समुदायों तक पहुंचनी चाहिए। 'स्वास्थ्य पर चर्चा' के माध्यम से हमारा उद्देश्य लोगों को निवारक देखभाल की सही जानकारी देना है, ताकि बीमारियों का समय रहते पता लगाकर उनका प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रितेश गुप्ता विधायक शहर, विनोद अग्रवाल महापौर और कुमार रणविजय सिंह एसपी सिटी मुरादाबाद उपस्थित रहे। इनके अलावा विशिष्ट अतिथियों में उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता व प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव अग्रवाल सहित मुरादाबाद इकाई के सदस्य शामिल रहे।

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'कौन बनेगा बिजनेस लीडर' प्रतियोगिता का आयोजन सम्पन्न

मेजा, प्रयागराज।

उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उरूवा विकासखंड के रामनगर गांव में 'कौन बनेगा बिजनेस लीडर' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम महिला आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को तकनीकी सुविधा, बाजार से संपर्क, क्षमता वृद्धि, ऋण सुविधा तथा उद्यमी सहायता केंद्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इन माध्यमों से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक विकास अधिकारी (ग्रामीण) कमलेश कुमार सिंह तथा खंड मिशन प्रबंधक विनय कांत शुक्ला ने किया। स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति के कार्यक्रम प्रबंधक प्रशांत श्रीवास्तव ने उद्यमिता विकास एवं उद्यम स्थापना से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक भी किया गया। कलाकारों ने अभिनय के माध्यम से स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित महिलाओं और युवाओं ने सराहा। संस्था के सहायक कार्यक्रम प्रबंधक पीयूष रंजन और हर्ष सिंह ने बताया कि परियोजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जा रहा है। गांव-गांव में सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में कम समय में अधिक उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। प्रतियोगिता में तीन विकासखंडों के विभिन्न गांवों से लगभग 250 से 300 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। अंत में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

जिला स्तरीय त्रैमासिक टीबी टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

छह वर्ष से कम आयु के टीबी ग्रस्त बच्चों को दोगुना पोषाहार देने के दिये गये निर्देश

बहराइच।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय त्रैमासिक टीबी टास्क फोर्स बैठक की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी मुकेश कुमार ने टीबी उन्मूलन अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से छह वर्ष से कम आयु के टीबी से ग्रसित लगभग 28 बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मानक से दोगुना पोषाहार उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि उनकी रिकवरी तेज हो सके और कुपोषण की समस्या दूर हो। सीडीओ ने टीबी मरीजों को गोद लेने की पहल को और व्यापक बनाने के लिए पोषण किट की मानक सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सूची अन्य विभागों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण सहयोग प्रदान कर सकें और उपचार के दौरान उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। इस बैठक में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. एम.एल. वर्मा ने बताया कि जनपद की लगभग 121 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2025 में 264 लोगों ने आगे आकर 7200 टीबी मरीजों को गोद लिया और उन्हें पोषण किट व मानसिक संबल प्रदान किया। बैठक के दौरान शरणं संस्थान के प्रतिनिधियों ने एचआईवी/एड्स पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि माइग्रेंट आबादी, नशे की लत से ग्रसित लोग और सेक्स वर्कर्स के माध्यम से इस रोग के प्रसार की संभावना अधिक रहती है। एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों में टीबी होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए ऐसे रोगियों की अनिवार्य रूप से टीबी जांच कराई जानी चाहिए। सीएमओ डॉ संजय कुमार ने बताया कि जनपद में निजी क्षेत्र से टीबी नोटिफिकेशन लक्ष्य से कम है। वर्ष 2025 के लिए निर्धारित 2919 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 2443 मरीजों का ही पंजीकरण हो पाया है। उन्होंने आईएमए/आईएपी के चिकित्सकों से सभी टीबी मरीजों का निःक्षय पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने और अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। इस अवसर पर डीएचईआईओ बृजेश सिंह, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, जेल प्रशासन, पुलिस विभाग, रेड क्रॉस सोसायटी, बाल एवं पुष्टाहार विभाग तथा शिक्षा विभाग सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आप पर कसा तंज, कहा- सौरभ भारद्वाज खुद ही कर रहे सेल्फ गोल

नई दिल्ली । दिल्ली में बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी (आप) और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज को अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम हजम नहीं कर पा रही है. इसी वजह से आप के नेता लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली को राहुल गांधी की तरह एक नया नेता मिल गया है, जो अब सौरभ भारद्वाज के रूप में सामने आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज खुद ही सेल्फ गोल कर रहे हैं और हर मामले में बीजेपी को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं.

इस मामले में सेल्फ गोल कर रहे सौरभ भारद्वाज- हरीश खुराना

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि जिस मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारद्वाज सेल्फ गोल कर रहे हैं. यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि साल 2020 से जुड़ा हुआ है. उस समय दिल्ली में आप की सरकार थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे. इसके अलावा जिस एपीजे स्कूल का जिक्र किया जा रहा है, उसमें 2025 में बच्चों के रोल नंबर रोके गए थे. उस वक्त भी दिल्ली में आप की ही सरकार थी और मुख्यमंत्री आतिशी थीं. आप नेताओं ने

मैनेजमेंट कोटे के तहत कराए बड़े पैमाने पर एडमिशन

हरीश खुराना ने साफ कहा कि अब बीजेपी सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसके तहत किसी भी बच्चे का रोल नंबर नहीं रोका जा सकता. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार जो नया बिल लेकर आई है. उसका विरोध कौन-सी एनजीओ कर रही है और उस एनजीओ का संबंध सौरभ भारद्वाज से क्यों जुड़ा हुआ है. उन्होंने उस एनजीओ का नाम जस्टिस फॉर ऑल बताया. बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि आप के नेताओं ने मैनेजमेंट कोटे के तहत बड़े पैमाने पर एडमिशन कराए हैं. उन्होंने पूछा कि जब आपकी सरकार थी, तब आपने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया, जिससे इन गड़बड़ियों पर रोक लगती है.

एडमिशन की सूची सार्वजनिक करेंगी सीएम- खुराना

हरीश खुराना ने यह भी कहा कि जल्द ही रेखा सरकार मैनेजमेंट कोटे से कराए गए सभी एडमिशन की सूची सार्वजनिक करेगी. इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जस्टिस फॉर ऑल एनजीओ का आप से क्या रिश्ता है. इसकी जांच होनी चाहिए और इस एनजीओ को मिलने वाली फंडिंग कहां से आ रही है, इसकी भी दिल्ली सरकार द्वारा पूरी जांच कराई जाए.

5 राज्यों में चुनावी शंखनाद की तैयारी, चुनाव आयोग मार्च के मध्य में कर सकता है तारीखों का ऐलान

नई दिल्ली । भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम मार्च के मध्य में घोषित कर सकता है।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान अप्रैल में अलग-अलग तारीखों पर होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग सभी पांच विधानसभाओं के चुनाव की तारीखें मार्च के मध्य में एक साथ घोषित करने की योजना बना रहा है। हालांकि, मतदान राज्य के अनुसार कई चरणों में भी हो सकता है। पांचों विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 20 मई, 23 मई, 10 मई और 7 मई को समाप्त होगा। चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव वाले राज्यों का दौरा कर रहा है। चुनाव आयोग की एक टीम वर्तमान में असम में चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में, पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान हुआ था, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक था। असम में दो चरणों में मतदान हुआ, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक-एक चरण में चुनाव हुए थे। तैयारियों के तहत, मतदाता सूचियों के संशोधन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है। मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत पुडुचेरी ने 14 फरवरी को अपनी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने वाला पहला राज्य था। तमिलनाडु मंगलवार को एसआईआर के बाद अपनी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने वाला है, जबकि केरल 21 फरवरी को अपनी अंतिम सूची जारी करेगा। पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। असम में, जहां एसआईआर के बजाय मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन किया गया था, अंतिम सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की गई थी।

बंगाल में एसआईआर पर सियासत जारी

चुनाव आयोग बना तुगलकी आयोग, राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम रहा- ममता

कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यभर की राजनीति में गर्माहट तेज है।

चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। हालांकि राज्य में जारी गहमागहमी का का एकमात्र कारण चुनाव नहीं है।

इसका बड़ा कारण राज्य में चल रहे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भी है। ऐसे में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर कोलकाता में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब तुगलकी आयोग बन गया है और किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा आईटी सेल की एक महिला पदाधिकारी ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिए। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहा है, वोटरों को निशाना बना रहा है और लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी।

तारिक रहमान ने बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली

ढाका। तारिक रहमान ने मंगलवार को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद देश की बागडोर संभालने वाली अंतरिम सरकार के 18 महीने के शासन का अंत हो गया. राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने रहमान (60) को परंपरा से हटते हुए, बंगभवन के बजाय जातीय संसद के 'साउथ प्लाजा में पद की शपथ दिलाई. रहमान के साथ 25 मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पुत्र रहमान 17 वर्षों तक स्वनिर्वासन में लंदन में रहने के बाद दो महीने पहले स्वदेश लौटे थे. प्रधानमंत्री के पद पर उनका कार्यकाल पांच वर्षों का होगा. दिन में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के सांसदों ने रहमान को संसदीय दल का नेता चुना. राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने एक समारोह में, मंत्रिमंडल के नये सदस्यों को भी शपथ दिलाई. कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के कई नेता उपस्थित थे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

आधी रात गायब हुआ पूरा परिवार, दो महिलाएं और पांच बच्चे लापता, सीसीटीवी में मिले सुराग, तलाश जारी

औरैया । औरैया जिले में बिधूना कोतवाली क्षेत्र के गांव बम्हारा में मंगलवार तड़के हड़कंप मच गया। यहां एक ही परिवार की दो महिलाएं अपने पांच बच्चों के साथ घर से लापता हो गईं। एक साथ सात लोगों के अचानक लापता होने से गांव सहित क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बंधरा निवासी आशीष ने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबह करीब चार बजे जब परिवार के लोग जागे, तो घर में दो महिलाएं और बच्चे नहीं मिले। काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कहीं पता नहीं चला, तो परिजन के हाथ-पांव फूल गए। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाओं के पति बाहर रहकर नौकरी करते हैं और घर पर महिलाएं व बच्चे ही थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाल मुकेश बाबू चौहान फोर्स के साथ गांव पहुंचे। गांव के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाले। इस दौरान दोनों महिलाएं अपने बच्चों के साथ पैदल जाती दिखाई दीं। फुटेज के आधार पर पुलिस की दो टीम उनकी तलाश में जुट गई है। बाहर रह रहे दोनों महिलाओं के पति को सूचना दे दी गई। दोनों घर के लिए चल दिए। इसी दौरान पुलिस को गांव कौरतपुर में एक बैग मिला, जिसे जांच के बाद परिजन को सौंप दिया गया।

सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, सुकमा में 22 नक्सलियों ने डाले हथियार; एक महिला भी

सुकमा । नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुकमा जिले में 22 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। इस घटना को नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। आत्मसमर्पण की यह प्रक्रिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित शाह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस बड़ी सफलता में जिला रिजर्व गार्ड, जिला पुलिस बल, क्षेत्रीय फील्ड टीम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोबरा बटालियन की सराहनीय भूमिका रही। सुरक्षाबलों द्वारा लंबे समय से चलाए जा रहे सघन तलाशी व घेराबंदी अभियानों के कारण नक्सली संगठनों पर लगातार दबाव बना हुआ था।

पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने छोड़े हथियार

प्रशासन के अनुसार, सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति, बेहतर जीवन की संभावनाओं और विकास कार्यों के विस्तार से प्रभावित होकर नक्सलियों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नियमानुसार पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में नक्सलवाद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास का माहौल और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। यह कदम क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

अहमदाबाद, वडोदरा सहित गुजरात के 6 कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी; मचा हड़कंप

नई दिल्ली। गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। अधिकारियों के मुताबिक, अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड, राजकोट, गांधीनगर और मेहसाणा की कोर्ट को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। बम की धमकी मिलने बाद अधिकारियों ने सभी अदालतों की तलाशी ली। हालांकि जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजे गए एक ईमेल में दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर में बम रखे गए हैं। डीसीपी, जोन 2 मनीता वंजारा ने कहा, मेल में लंच टाइम तक कोर्ट परिसर में बम लगाने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने तमिलनाडु कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। वडोदरा स्क्वॉड, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड, लोकल पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम सुबह करीब 11 बजे मौके पर पहुंची। कोर्ट परिसर को घेर लिया गया और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वलसाड के पुलिस सुपरिटेंडेंट युवराज सिंह जडेजा ने बताया कि वलसाड में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 19 कोर्ट रूम खाली करा लिए गए, क्योंकि एक ईमेल में दावा किया गया था कि कोर्ट में 19 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाए गए हैं, जो दोपहर की नमाज से पहले ब्लास्ट करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सर्च के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि राजकोट, गांधीनगर और अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मंगलवार सुबह खाली करा लिए गए, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दोपहर में, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद उसे खाली करा लिया गया।

चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की घर वापसी की जमीन तैयार करने में जुटा भाजपा नेतृत्व, विरोध में कई नेता

नई दिल्ली । पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सिद्धू दंपती की घर वापसी की जमीन तैयार करने में जुटी है। नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर को वापस लाने के लिए रोडमैप करीब-करीब तैयार किया जा चुका है। शीर्ष नेतृत्व जल्द ही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया जैसे सिद्धू विरोधी पार्टी नेताओं से बात करेगा। सूत्र ने बताया कि फिलहाल इस संबंध में प्रारंभिक बातचीत हुई है। कांग्रेस से पत्नी के निष्कासन के बाद सिद्धू फिलहाल कांग्रेस में हैं मगर यह दंपती लगातार कांग्रेस और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधने के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है। सूत्र का कहना है कि इस संबंध में इसी महीने के अंत तक अंतिम फैसला हो सकता है।

पंजाब सीएम भगवंत मान को जहरीला केमिकल पोलोनियम देने का दावा

खालिस्तानी आतंकियों ने बेअंत सिंह जैसा हाल करने की धमकी दी, भगवंत मान अस्पताल में भर्ती

मोहाली । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी गई है। खालिस्तान समर्थक संगठन, खालिस्तान नेशनल आर्मी ने प्रशासन को ईमेल भेजकर धमकी दी कि हमने मान को भाई दिलावर सिंह के वारिसों ने पोलोनियम से संक्रमित किया है। अगर वे बच गए तो उनका पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा हाल करेंगे। सीएम मान मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। खालिस्तान नेशनल आर्मी ने इस अस्पताल समेत 16 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी। मोहाली के एसपी सिटी दिलप्रीत सिंह ने ईमेल की पुष्टि की है। एसपी का कहना है कि धमकी भरा ईमेल आया है। हम सभी चीजों को वैरिफाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अस्पताल को अच्छी तरह से जांच की गई है। सब सेफ है। सीनियर्स के अगले आदेश तक फोर्स को हॉस्पिटल में तैनात रखा जाएगा। एसपी दिलप्रीत सिंह ने बताया कि मेल में ब्लास्ट का टाइम दोपहर 1.11 बजे दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह साढ़े 7 बजे थ्रेट मेल मिलते ही फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों की जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली लेकिन चांस नहीं लिया जा सकता। सीएम मान को जिस पोलोनियम केमिकल देने की बात सामने आई है, वह दुर्लभ रेडियोएक्टिव पदार्थ है। यह बहुत जहरीला होता है। हालांकि, सीएम को पोलोनियम से संक्रमित कब, कहां और कैसे किया गया, खालिस्तान नेशनल आर्मी की मेल में इसका कोई जिक्र नहीं है। सीएम मान रविवार को ब्लड प्रेशर बढ़ने पर मोहाली फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए थे।

फिर सोमवार को डिस्चार्ज होकर मोगा में आप सरकार की नशा विरोधी रैली में हिस्सा लेने गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोगा में सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें सोमवार शाम करीब 5 बजे उन्हें फिर मोहाली फोर्टिस में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने उनकी सेहत को लेकर कोई बुलेटिन जारी नहीं किया। पंजाब में एक हफ्ते के अंदर खालिस्तान नेशनल आर्मी ने इस तरह की धमकी वाली ये दूसरी मेल भेजी है। इससे पहले 11 फरवरी को भी संगठन ने मेल भेजकर दावा किया था कि पंजाब सीएम को 13 फरवरी को मानव बम से उड़ाया जाएगा। उस मेल में भी कुछ स्कूलों को धमकी दी गई थी। खालिस्तान नेशनल आर्मी ने अपनी मेल में जिस दिलावर सिंह का जिक्र किया है, वह एक कॉन्स्टेबल था जिसने 31 अगस्त 1995 को पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह को चंडीगढ़ सचिवालय में मानव बम से उड़ा दिया था। हेटर फार्ले के नाम से जीमेल के जरिए भेजे ई-मेल में पंजाब को खालिस्तान बताते हुए कहा गया है अपने बच्चों बचा लो और मोहाली के स्कूल बंद रखो। मेल में लिखा गया है कि यह खालिस्तान रेफरेंडम वालों को गैंगस्टर बताकर उनका एनकाउंटर लेने का बदला है। मेल के अंत में खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम लिखा है। इसके साथ इंजीनियर गुरनाख सिंह, स्वर्ण शाहवाला, डॉ. गुरुस्वीर सिंह और खान रजादा का जिक्र है। हालांकि इससे पहले भी कई बार अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मोहाली और चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन हर बार यह खोखली निकली। इस बार स्कूलों के साथ सीएम भगवंत मान को लेकर भी धमकी दी गई।

भारत फ्रांस साझेदारी की कोई सीमा नहीं - पीएम मोदी

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसका उद्देश्य भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। यह वार्ता महाराष्ट्र लोक भवन में हुई, जहां दोनों नेताओं ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते हुए आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक राष्ट्रपति मैक्रॉन की भारत की चौथी यात्रा के अंतर्गत हुई। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत की वित्तीय राजधानी में अपने अनुभव साझा किए और कहा कि मैक्रॉन को यह शहर पसंद आया और उन्होंने सुबह की दौड़ का आनंद लिया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, मुंबई में अपने मित्र, राष्ट्रपति मैक्रॉन से मिलकर बहुत खुशी हुई! उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें यह शहर बहुत पसंद आया और उन्होंने सुबह की दौड़ का भी आनंद लिया।- दोनों नेताओं ने अपनी वार्ता से पहले मुंबई के लोकसभा भवन में मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की। दोनों नेताओं को एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए सौहार्दपूर्ण बातचीत करते देखा गया। आज सुबह मुंबई में सुबह की चहल-पहल शुरू होने के समय, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सुबह की सैर में शामिल होकर मुंबईवासियों को चौंका दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को फ्रांसीसी और भारतीय अधिकारियों सहित सुरक्षाकर्मियों के एक दल के साथ जॉगिंग करते देखा गया। यह जॉगिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और रास्ते में मीडिया और स्थानीय लोगों की ओर से कोई खास व्यवधान नहीं हुआ। उसी दिन, आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को दर्शाते हुए एक मार्मिक क्षण में, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन ने अपने आगमन पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस भाव ने कट्टरता और हिंसा के घावों का सामना कर चुके दो देशों के बीच एक सेतु का काम किया, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रॉन ने लचीलेपन और लोकतंत्र के उन साझा मूल्यों पर जोर दिया जो नई दिल्ली और पेरिस को आपस में जोड़ते हैं।

भारत और फ्रांस दोनों प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत और फ्रांस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, लोथल पर सहयोग करेंगे, और पहले ही व्हेल म्यूजियम पर साथ काम किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय संस्कृति को फ्रांस के लोगों के करीब लाने के लिए जल्द ही स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर फ्रांस में खोला जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का भारत-फ्रांस साझेदारी के प्रति गहरा समर्पण है और आज दोनों देशों ने अपने रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू किया है। उन्होंने विश्व स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने का भी संदेश दिया।

मैक्रों बोले- दोनों देशों ने आज इस साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया

राष्ट्रपति मैक्रों ने बताया कि दोनों देशों ने आज इस साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है, जिससे इसे नया महत्व मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में दोनों देशों ने अलग-अलग क्षेत्रों में कई नई पहल की हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र हो, नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी परियोजनाएं हों, दोनों देशों ने मिलकर कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी कहा कि दोनों देश कानून का सम्मान करते हैं और किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार नहीं होने पर विश्वास रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस की साझेदारी एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम बहुपक्षीय डायलॉग पर जोर देना जारी रखेंगे। हम एकमत हैं कि वैश्विक संस्थानों के सुधारों से ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या वैश्विक दक्षिण हम हर समस्या के हल के लिए साथ काम करते रहेंगे। भारत और फ्रांस दोनों ही प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं हैं। हम जल्द ही फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर खोलने जा रहे हैं। भारत-फ्रांस पार्टनरशिप को लेकर आपकी गहरी प्रतिबद्धता रही है।